

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1359-दो/2006 – विरुद्ध – आदेश दिनांक  
27-1-2006 पारित – द्वारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – –  
प्रकरण क्रमांक 521/बी-121/2002-03 अपील

रामशरण पुत्र रामगोपाल नामदेव  
निवासी ग्राम ओरछा तहसील निवाड़ी  
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

विरुद्ध

—आवेदक

- 1– नाथूराम पुत्र हलके काढी  
निवासी ओरछा मोहल्ला तकिया नरिया  
तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़
- 2– रमेश चंद पुत्र हीरालाल जैन  
द्वारा फूलचंद कन्छेदीलाल बछरावनी वालों  
के मकान में तथा संतोष किराना स्टोर  
के बगल में डोडाघाट तालावपुरा ललितपुर  
उत्तरप्रदेश

—अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव  
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर

आदेश

(आज दिनांक 19.8.2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 521/बी-121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2006 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, टीकमगढ़ के

*Omkar Singh*

समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम ओरछा की भूमि खसरा नंबर 557/1/2 रक्का 4.492 हैक्टर के रक्का 0.700 है. पर वह 1980-81 से कब्जा किये हुआ है किन्तु अनावेदक क्रमांक-1 पटठाधारी ने इस भूमि का विक्य अनावेदक क्र-2 को बिना सक्षम अनुमति के कर दिया है इसलिये विक्य पत्र को शून्य घोषित किया जावे। कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 13 बी 121/2002-03 पंजीबद्व किया एंव वाद जांच पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 20-2-2003 पारित किया तथा आवेदक का दावा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार के अंतर्गत नहीं पाये जाने से निरस्त कर दिया।

कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 13 बी 121/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 20-2-2003 के विरुद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 521/बी-121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

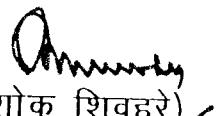
3/ आवेदक के अभिभाषक ने बहस के दिन बताया कि उनका पक्षकार से कोई संपर्क नहीं है इसलिये उन्हें निगरानी में पक्ष नहीं रखना है। अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष आवेदक की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया गया है।

और कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 13 बी 121/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 20-2-2003 से आवेदक का दावा निरस्त किया है अर्थात् कलेक्टर न्यायालय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7)(ख) एवं धारा 182 (2) दो व चार का दावा सुनने हेतु मूल न्यायालय रहा है कलेक्टर के आदेश दिनांक 20-2-2003 के विरुद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत हुई है जो आदेश दिनांक 27-1-2006 से निरस्त हुई, जिसके विरुद्ध विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत की गई है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 44 – कलेक्टर द्वारा संहिता, 1959 की धारा 165 (7)(ख) एवं धारा 182 (2) के अंतर्गत मूल न्यायालय की हैसियत से पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी। आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में होगी।  
स्पष्ट है कि विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है, जो न्यायालय में दिनांक 28-7-2006 से दायर होकर निगरानी को अपील में बदलकर सुने जाने की प्रार्थना भी नहीं की गई है और निगरानी को अपील में बदलकर सुने जाने हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर ~~अनुशासनी~~ अग्राह्य होने से अगान्य की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 521/बी-121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2006 रिथर रहता है।

  
(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर